श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, इन मकानात को किन लोगों ने किराये पर ले रखा है और उनके नाम क्या है । उन्होंने जिस समय इन इमारतों को किराये पर लेना चाहा, तो किस परपज के लिए उन्हें इस्तेमाल करना उन्होंने बताया, क्या माननीय मन्त्री जी उसे बतलाने की कृपा करेगे ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : ये पहले से ही अच्छे कामों के लिये इस्तेमाल नहीं हो रही थी । तब जो किराया वसूल हो रहा था वह इजारेदारों के मारफत वसूल हो रहा था और अब भी इजारेदारों के मारफत ही हो रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, यह सब जानते हुए कि ये इमारतें इललीगल कामों के लिये इस्तेमाल की जा रही है, क्या सरकार का यह कर्तव्य नही है कि उनके बारे मे फिर से इन्क्वायरी करके इन लोगों को इवैक्यूएट कराये, जो सरकारी इमारतों का इस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इवैक्यू प्रौपर्टी ला की दफा १२ के नीचे जो प्रौपर्टी हमारे कब्जे मे आई है, वह लीगल तरीके से आई है और जो उसका रिजल्टेंट आब्लीगेशन है, वह हमें उसी ला के मुताबिक डिसचार्ज करना पडता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, यह बात सही है कि जिस ला के नीचे ये प्रौपर्टी आई है उसी के मुताबिक इस्तेमाल करना पडता है । लेकिन क्या यह उचित न होगा कि ऐसी स्थिति में जब कि ये सरकारी बिल्डिग्ज जो कि इवैक्यू प्रौपर्टी के अन्तर्गत आ चुकी है, ब्रौथल की तरह इस्तेमाल की जा रही है, तो सरकार इस मामले पर गौर करे और इन लोगों को तुरन्त इवैक्यूएट कराये ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जनाब वाला, ये मकान बहुत जल्द बेचे जायंगे । आगे ये मकानात किस चीज के लिये इस्तेमाल होंगे, यह बात मेरे काबू के बाहर है ।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : श्रीमन्,माननीय मंत्री महोदय का जो उत्तर है उससे यह मालूम होता है कि जो इवैक्यू प्रौपर्टी है वह सचमुच में अच्छे काम के लिये नही बल्कि खराब काम के लिये इस्तेमाल हो रही है । क्या यह बात उनके नालेज में है, क्या यह बात ठीक है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह दुरुस्त नहीं है । हमारे पास इस वक्त जो इवैक्यू प्रौपर्टी है वह तकरीबन १०० करोड रुपये की है । उसमें २३७ मकानात काठ बाजार में है । उनमें चन्द ऐसे है जो निष्क्रान्त है, बाकी तमाम जायदाद अच्छे काम के लिये इस्तेमाल हो रही है । हम उनमें रिफ्यूजीज को बसा रहे है और उनको मालिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, क्या यह उचित नही होगा कि जब तक सरकारी तौर से उन्हें बेचा नही जाता, तब तक सरकार ऐसी कार्यवाही करे कि इन सरकारी इमारतो में इस तरह का इम्मौरल ट्रैफिक न हो ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरे खयाल में यह सवाल हैल्थ मिनिस्ट्री या दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है । मै जल्दी ही इन मकानात को बिकवाने वाला हूं ।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, क्या सरकार को यह विदित है कि जो ठेकेदार इन बिल्डिगों को इस्तेमाल करते है वे आम तौर से लोगो से यह कहते है कि हमको इस काम के लिये सरकार की स्वीकृति और सहमति प्राप्त है । क्यो हम सरकारी बिल्डिगों में इस तरह के चकले चला रहे हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने अभी बतलाया कि ये ठेकेदार पुराने है । मेरी उनसे कोई जाती वाकफियत नही है ।

ASSISTANCE FROM NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

*133. SHRI M. VALIULLA : Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state :

(a) how many persons and firms received assistance from the National Industrial Development Corporation Ltd., up to 31st March 1956.

(b) for what purpose the assistance was used ; and

(c) what work has been done by the recipients in furtherance of the objects for which the assistance was received ?

THE MINISTER FOR HEAVY INDUSTRIES (SHRI M. M. SHAH): (a) and (b). Assistance from the National Industrial Development Corporation Private Ltd., is for the present confined to the grant of loans to cotton textile and jute industries for purposes of modernisation and rehabilitation of plant and machinery. No amounts were paid by the Corporation till the 31st March 1956.

(c) Does not arise.

SHRI M. VALIULLA : What was the capital of this Corporation to start with and how much has been added every year ?

SHRI M. M. SHAH : Rs. 1 crore capital. It is a private limited company.

SHRI M. VALIULLA : May I know whether the entire capital was given at one and the same time or it is added to year by year ?

SHRI T. T. KRISHNAMACHARI : That is the procedure. We add each year whatever amount is required for the capital needs of this particular Corporation.

MR. CHAIRMAN : Because the Minister is so close to you, you are talking in a low tone ; both the questioner and the Minister who answers may speak a little louder.

SHRI M. VALIULLA : May I know why it is that no loans or assistance have been given ? Is it because investigations are going on into the industries ?

SHRI M. M. SHAH : Two Committees are functioning for this purpose, one for cotton textiles in Bombay and the other for jute in Calcutta. Eleven applications for jute have been received and are under consideration, and 14 applications for textile mills are being surveyed.

SHRI M. VALIULLA : What is the total amount that these 11 companies have asked for ?

SHRI M. M. SHAH : The total amount asked for jute is Rs. 2,70,00,000

SHRI B. P. AGARWAL : May I know whether any rules have been framed for the granting of assistance ?

SHRI T. T. KRISHNAMACHARI : Yes, Sir, Rules have been framed. In fact, the Corporation has sanctioned loans to two jute companies to the tune of Rs. 25 lakhs and Rs. 29 lakhs respectively but the companies have not yet taken advantage of this, because they have not completed the documents.

INDUSTRIES RECEIVING AID FROM INDUSTRIAL AID COMMITTEE IN TRAVANCORE-COCHIN

*134 { SHRI GOVINDAN NAIR : / SHRI J. V. K. VALLABHARAO:

Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of the industries receiving aid from the Industrial Aid Committee in Travancore-Cochin ;

(b) the names of the concerns that received such aid in 1955-56 ; and

(c) whether Government have examined the working and progress of the concerns receiving such aid ?

THE MINISTER FOR HEAVY INDUSTRIES (SHRI M. M. SHAH): (a) A statement is placed on the Table of the House.

(b) A statement containing names of some of the institutions that received such aid in 1955-56 is laid on the Table of the House. Names of other societies and institutions will be placed before the House when received.

(c) Information when received from Travancore-Cochin State will be placed before the House.

STATEMENTS

Names of industries receiving aid from the Industrial Aid Committee in Travancore-Cochin State

1. Oils
2. Coir industry
3. Handloom industry
4. Leather
5. Cutlery
6. Bamboo goods